

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- चित्तौड़गढ़ में RSBCL का डिपो मैनेजर (लेखाधिकारी) 18 हजार 200 रुपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 09 अगस्त बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रविन्द्र पारीक, डिपो मैनेजर, (लेखाधिकारी), RSBCL, डिपो चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 18 हजार 200 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि शराब लाने वाले ट्रक स्वामियों द्वारा माल को शीघ्र उतरवाने हेतु श्रमिकों को दिये जाने वाले उपहार राशि में से अपने स्वयं के लिये रविन्द्र पारीक, डिपो मैनेजर, (लेखाधिकारी), RSBCL, डिपो चित्तौड़गढ़ द्वारा 18 हजार 200 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के सुपरवीजन में एसीबी की चित्तौड़गढ़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाश सान्दू के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये रविन्द्र पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक, उम्र 58 साल, निवासी म.नं. 10, RC व्यास नवजीवन पब्लिक स्कूल के पास भीलवाड़ा हाल डिपो मैनेजर, (लेखाधिकारी), RSBCL, डिपो चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 18 हजार 200 रुपये नगद राशि रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।